

>

Title: Need to bring the denotified tribes into the mainstream of the country.

श्री रमाशंकर राजभर (सलेमपुर): इस देश में अंग्रेजों ने कुछ जातियों को क्रिमिनल एक्ट में निरूद्ध किया था, उनकी प्रान्तवार सूची नितान्त आवश्यक है। निरूद्ध जातियों को किस आयोग के तहत विमुक्त किया गया था। आयोग की सिफारिशें क्या थी? इन जातियों को देश के आरक्षण में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग में प्रान्तवार किस आरक्षण कोटे में रखा गया है। यह जातियाँ विमुक्त धारा से मुक्त होने के बाद भी आज तक किसी प्रान्त में किसी भी आरक्षण कोटे में नहीं हैं। मेरी मांग है कि सरकार विमुक्त जातियों के विकास के लिए कोई प्रावधान करे एवं उन्हें सुविधाएँ दें तथा आवश्यक प्रमाण पत्र प्रदान करें। देश की आजादी में लड़ने वाले क्रिमिनल एक्ट में निरूद्ध इन जातियों की वर्तमान स्थिति के बारे में जानकारी दी जाये। सरकार ने इन्हें विनियमित कर समाज के मुक्त धारा में लाने का प्रयास करें।